जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 13 संख्याः 274 प्रभात चूरू, मंगलवार 1 फरवरी, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

एक शोध में सामने आया है कि पृथ्वी पर मौजूद ''अंतिम'' जंगली घोड़े विशुद्ध जंगली नहीं हैं। मंगोलिया में मिलने वाले शिवाल्स्की घोड़े, जिन्हें अब तक जंगली घोड़ों की आखिरी बची हुई प्रजाति माना जाता था, असल में जंगली नहीं हैं बल्कि भाग कर जंगल में आए पालतू घोड़ों के वंशज हैं। इसका अर्थ है कि जंगली घोड़े पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। इस रिसर्च ने पालतू घोड़ों के उद्गम के रहस्य को उलट कर रख दिया है। वर्तमान में मंगोलिया में 2000 शिवाल्स्की घोड़े हैं। फ्रैंच नैशनल सैंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर लुडोविक ऑरलैण्डो ने कहा कि ''हमारे नतीजों ने घोड़ों के उद्गम में वर्तमान सिद्धांतों को पलट दिया है। नए शोध का दावा है कि शिवाल्स्की घोड़े, जिन्हें 20 वीं सदी में लुप्त होने से बचाया गया था, असल में उन घोड़ों के वंशज हैं जिन्हें साढ़े पांच हजार साल पहले उत्तरी कज़ाकस्तान में रहने वाले बोताई संस्कृति के लोगों ने पालतू बना लिया था। रिसर्च में सामने आया कि बोताई संस्कृति में घोड़ों को पालतू बनाने के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। युनिवर्सिटी ऑफ कैन्सस की सैन्ड्रा ओल्सन, जो इस शोध में शामिल हैं, ने कहा कि ''वास्तविक जंगली घोड़े हजारों साल पहले तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले अवश्य ही लुप्त हो गए थे। पर हमें यह सत्य अभी पता चला है।'' शोधकताओं ने बताया कि बोताई आदिवासियों द्वारा पालतू बनाए गए कुछ घोड़े जंगल में भाग गए थे और यही शिवाल्स्की घोड़े थे। इंसान और घोड़ों का संबंध सैकड़ों साल पुराना है और घोड़ों को पालतू बनाना एक महत्वपूर्ण खोज थी। पांच सौ साल पुराने ताम्र युग से लेकर स्टीम इंजन की शुरुआत तक घुड़सवारी ही यातायात का सबसे तेज रफ्तार जरिया थी। मोटर कार आने के बाद यातायात के लिए घोड़ों का इस्तेमाल कम हुआ। इंसान की गतिशीलता, व्यापार और युद्ध कौशल में घोड़े से ही नई क्रांति आई थी।

इकोनॉमिक सर्वे इस बार रहस्यमय उलझन है, जो पहेली के लिहाफ में लिपटी है

केन्द्रीय सरकार की रैवेन्यु (आमदनी) में, उदाहरण के लिये, अप्रेल-नवम्बर में 67.2 प्रतिशत ग्रोथ हुई, जबकि 2020-21 के बजट में केवल 9.6 प्रतिशत ग्रोथ की आशा की गयी थी

- दूसरी ओर टैक्स कलैक्शन में जिनका अधिकांश योगदान होता है, वो सैक्टर अभी तो केवल प्री-पैन्डैमिक स्टेज (महामारी से पहले की स्थिति) तक पहुंचे ही हैं।
- अतः अहम् सवाल है, इकॉनमी में यह ग्रोथ कहां से आयी?
- सरकार की ओर से मुख्य इकोनॉमिक सलाहकार, संदीप सन्याल ने इस सवाल के जवाब में कहा, ''भारत की इकॉनमी पर ''रिकवरी'' (उछाल) का कारण है, जिस रचनात्मक व तत्परता से सराकर ने महामारी पर नियंत्रण पाने के लिये कदम उठाये।
- पर जानकार लोगों का कहना है, देश के उद्यमी, उद्योगपतियों की बेसिक ''एनिमल स्पिरिट'' है, जिसने इकॉनमी को खड्डे में धंसने से रोका, अतः आगामी बजट में ऐसे निर्णय और प्रयास दिखने चाहिये कि, सरकार इस ''एनिमल स्पिरिट'' को मजबूती प्रदान करे, कमजोर न करे।
- इस ''एनिमल स्पिरिट'' का प्रतीक हैं ''स्टार्टअप''। भारत अभी ''स्टार्टअप्स'' की दृष्टि से दुनिया में तीसरे नम्बर पर है, चीन व अमेरिका के बाद।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। संसद में आज पेश किए गए आर्थिक सर्वे के बारे में कहा जा रहा है कि, यह रहस्य में लिपटी एक पहेली है।

सर्वे, अर्थव्यवस्था की एक उत्साहित तस्वीर पेश करता है और अच्छे टैक्स कलैक्शन की शोखी बघारता है, लेकिन जिन सैक्टर्स से टैक्स का अधिकांश कलैक्शन हुआ है, उनमें बस महामारी पूर्व के स्तर की ही रिकवरी बनी हुई है।

इण्डस्ट्रियल सैक्टर में गत वर्ष अप्रैल और नवम्बर माह के दौरान 17 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान किया गया है, लेकिन इसमें उसके पहले वाले साल में रहे 15 प्रतिशत से अधिक के संकुचलन की ही भरपायी हुई।

इण्डस्ट्रियल सैक्टर जी.डी.पी. का 28 प्रतिशत और सर्विस सैक्टर का 53 प्रतिशत है, अतः इनका संयुक्त प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। सर्विस सैक्टर वैश्विक महामारी से सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ है, खासतौर पर वो खण्ड जो मानव सम्पर्क पर निर्भर हैं।

इस सैक्टर में पिछले वर्ष रहे 8.4 प्रतिशत के संकुचलन की तुलना में इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा करेगी भाजपा

बघेल, कभी सपा में होते थे पर, फिर भाजपा में आ गये और अखिलेश की पत्नी को चुनाव में हराया था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। भाजपा ने सन्निकट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिये केन्द्रीय विधि राज्यमंत्री एस.पी.सिंह बघेल को मैदान में उतारा है।

पिछड़े वर्ग के बघेल, जो आगरा से लोकसभा सांसद हैं, जाति के गड़रिया हैं। वे कभी समाजवादी पार्टी में थे, और बाद में उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल को पराजित किया था।

मेहनतकश नेता बघेल की छवि ईमानदार एवं प्रतिबद्ध नेता की है। वे योगी सरकार में मंत्री थे लेकिन बाद में उनका चयन आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये किया गया, जहाँ से वे चुनाव जीत गए। मंत्रिमण्डल के पिछले फेरबदल में, उत्तर प्रदेश चुनावों को मद्देनजर रखते हुये, वे मंत्री बना दिये गये थे। उस समय उत्तर प्रदेश के कई सांसद मंत्री बनाये गये थे।

- बघेल बैकवर्ड समाज के हैं और परिश्रमी व ईमानदार होने की प्रतिष्ठा है।
- वे योगी सरकार में मंत्री थे, पर फिर आगरा से उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाया गया और फिर जीतने के बाद केन्द्रीय मंत्री बनाया, यू.पी. में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए।
- भाजपा की मंशा है कि, बघेल की सशक्त उम्मीदवारी से अखिलेश अपने चुनाव क्षेत्र में बंध कर रह जायेंगे।
- अखिलेश फिलहाल सबसे सक्रिय नेता हैं सपा में, जिन्होंने कई छोटी-छोटी पार्टियों से हाल ही में गठबंधन किया है। जयंत चौधरी से गठबंधन कर, जाटों को सपा के नजदीक लाये हैं। पर, अगर वे इन गठबंधनों को क्रियान्वित करने के लिये उपलब्ध नहीं हुए तो, सपा काफी दिक्कत में आ सकती है।

बघेल को अखिलेश के खिलाफ खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य, समाजवादी नेता को उनके चुनाव क्षेत्र में ही उलझाये रखने का है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संभवतः ऐसे इकलौते स्टार प्रचारक हैं, जो भारी भीड़ खींच रहे हैं तथा बहुत चुस्त प्रचार अभियान चला रहे हैं।

जाट वोट बैंक को गठबंधन में वापस लाने के लिये, उन्होंने जयन्त चौधरी के साथ चुनावी गठबन्धन किया है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में यू.पी. के जातीय नेताओं के साथ गठबन्धन भी किया है, जिससे उन्हें मदद मिलेगी।

पिछड़े वर्ग के कई वरिष्ठ नेतागण भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो ही गये हैं।

याद रखने योग्य बात यह है कि, पिछले चुनावों में पिछड़ा वर्ग एकजुट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैंने गांधी को क्यों मारा'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें फिल्म ''वाय आई किल्ड गांधी'' (मैंने गांधी को क्यों मारा) या उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने, महात्मा गांधी की हत्या के बाद चले मुकदमे की थीम पर बनायी गयी फिल्म पर रोक लगाने से इंकार किया।

आम सभाओं पर लगे प्रतिबंध कुछ ढीले हुए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। चुनाव आयोग ने सोमवार को राजनैतिक दलों या चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की खुले स्थानों पर होने वाली जन सभाओं में लोगों की अधिकतम संख्या को 500 से बढ़ाकर 1000, अथवा मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत, या स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एस.डी.एम.ए.) द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, की अनुमति प्रदान कर दी है। एक फरवरी से लागू होने वाली यह वृद्धि मतदान के सभी चरणों के लिये है।

- चुनाव आयोग के नये आदेशों के अनुसार अब आमसभाओं में एक हजार व्यक्ति भाग ले सकेंगे, एक फरवरी से।
- डोर-टू-डोर प्रचार में 10 व्यक्तियों की सीमा को बढ़ा कर 20 की।

आयोग ने घर-घर प्रचार में शामिल लोगों की संख्या भी बढ़ाकर 10

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस-आर.जे.डी. गठबंधन टूटने के कगार पर

तेजस्वी यादव ने संकेत दिये कि, आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारों पर कोई समझौता नहीं होगा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। जहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ''एकला चलो'' की नीति अपना रखी है, वहीं पड़ोसी राज्य बिहार में भी, पार्टी इसी प्रकार की प्रवृत्ति एवं स्थिति को विकसित करती प्रतीत हो रही है।

लालू यादव-सोनिया गांधी की नजदीकी में आई कमी के चलते, कांग्रेस और आर.जे.डी. का लम्बे समय से चला आ रहा गठबंधन निष्फल एवं समाप्त हो रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने, राज्य की 24 विधान परिषद सीटों के आगामी चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों की साझेदारी की संभावना को खारिज कर दिया है।

दोनों ही पार्टियों के संबंध, पिछले अक्टूबर से ही डांवाडोल हैं, जब आर.जे.डी. ने उन दोनों विधानसभा सीटों, जहाँ उप चुनाव हुये थे, के लिये उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय एकतरफा तथा अपने ही स्तर पर ले लिया था। अब तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी विधान परिषद सीटों पर चुनाव अपने ही बलबूते पर लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि, आर.जे.डी. यह स्पष्ट कर चुकी है कि

- हालांकि, यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि, राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव की पार्टी, आर.एल.डी. कांग्रेस के साथ रहेगी।

वह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन करेगी। उन्होंने पूछा, ''इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।''

कांग्रेस को इस तथ्य से सांत्वना मिल सकती है कि, सत्तारूढ़ पार्टी गठबंधन में भी गड़बड़ी है। एन.डी.ए. पार्टनर तथा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख, मुकेश साहनी उस फॉर्मूले से नाखुश बताये जाते हैं, जो भाजपा और जे.डी.यू. के बीच तैयार हुआ है। फॉर्मूले के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि, भाजपा तथा जे.डी.यू. क्रमशः 12 एवं 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तथा 1 सीट पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले एल.जे.पी. खेमे के लिये छोड़ दी जायेगी। साहनी ने अभी हाल में ही घोषणा की है, कि ''विकासशील इंसान पार्टी (वी.आई.पी.) विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं (एन.डी.ए.) दिखा दूंगा कि निषाद समुदाय क्या कर सकता है।'' उन्होंने आरोप लगाया है कि एन.डी.ए. नेतृत्व ने उनके प्रति निरादर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्साही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भण्डारी मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भण्डारी, जिन्होंने अपनी न्यायिक सेवा राजस्थान से ही शुरु की थी, को मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने, तथा 17 अन्य लोगों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मुनीश्वर नाथ भण्डारी राजस्थान के निवासी हैं, यहां ही ज्यूडिशरी से जुड़े थे।

'एयर इण्डिया को टाटा़ज़ को बेचने से पैसा तो मिला ही, सरकार की ''प्राइवटाइज़ेशन'' की मुहिम को बहुत मजबूती मिली'

निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री ने संसद में यह दलील देते हुए कहा, ''महामारी में सबसे बड़ा झटका ''सर्विस सैक्टर'' को लगा, जहां ''मानव से मानव का स्पर्श'' नियमित तौर पर होता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को लोक सभा के पटल पर रखा गया आर्थिक सर्वे यह रेखांकित करता है कि टाटा को किया गया एयर इण्डिया का विनिवेश ना केवल विनिवेश प्राप्तियां संचित करने में बल्कि निजीकरण अभियान में तेजी लाने के संदर्भ में भी विशेष महत्वपूर्ण रहा है।

इसमें कहा गया है कि वैश्विक महामारी से सर्विस सैक्टर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, खासतौर पर इसके वे भाग जिनमें मानव सम्पर्क जरूरी होता है। पिछले वर्ष हुए 8.4 प्रतिशत के संकुचन (कॉन्ट्रैक्शन) के बाद अब इस वित्त वर्ष में इसमें 8.2 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुमान है।

आर्थिक सर्वे कहता है कि घर खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। इसको लेकर उसके तर्क यह हैं:

-आवासों की बिक्री बढ़ाने के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने सर्किल रेट्स और स्टाम्प शुल्कों में कमी की हुई है।

-कोविड-19 की पहली लहर के दौरान आवास बिक्री के लेन-देनों में करीब-करीब सभी शहरों में कमी आयी थी। तथापि, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मुम्बई, थाणे, पुणे, नोएडा, हैदराबाद और बैंगलुरू जैसे कई शहरों में आवासन लेन-देनों में, महामारी के पूर्व के स्तर की तुलना में इजाफा हुआ था।

-गांधी नगर, अहमदाबाद, चेन्नई, रांची, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में महामारी पूर्व के स्तरों की तुलना में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आवासन लेन-देनों में कमी देखी गई। हालांकि यह कमी कोविड-19 की पहली लहर के दौरान रही कमी से काफी कम रही।

आर्थिक सर्वेक्षण में जिस महत्वपूर्ण थीम पर चर्चा की गई वह है ''प्रोसैस रिफॉर्म्स''। विनियमन और सुधारों की प्रक्रिया के बीच अन्तर आना महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विनियमन का संबंध एक गतिविधि विशेष से सहकार के संचालन को क्रय करना अथवा हटाना है, जबकि सुधारों की प्रक्रिया का संबंध उन गतिविधियों की क्रियाविधि को सरल और सुकर बनाना है, जहां एक व्यवस्थापक अथवा नियामक के रूप में सरकार की उपलब्धि अनिवार्य होती है। सर्वे में इस पर जोर दिया गया है कि, भारत में अमेरिका और चीन के बाद स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा ईको सिस्टम है। इसमें ध्यान दिलाया गया है कि, वर्ष 2016-17 में जहां 733 स्टार्ट अप्स थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 हजार नए स्टार्ट अप्स और जुड़े। वर्ष 2021 में भारतीय स्टार्ट अप्स की 44 रेकॉर्ड संख्या ने यूनिकॉर्न दर्जा प्राप्त किया, जिससे भारत में यूनिकॉर्न्स की कुल संख्या 83 हो गई। इनमें से अधिकांश स्टार्ट-अप्स सर्विस सैक्टर से हैं।

सर्वे में कहा गया है कि सारी दुनिया में ओमक्रॉन वैरिएन्ट के रूप में नई लहर फैल रही थी, अधिकांश देशों में महंगाई बहुत बढ़ गई थी तथा प्रमुख केन्द्रीय बैंक नकदी की वापसी के चक्र को शुरू कर रहे थे।

सर्वे इस बात को रेखांकित करता है कि यही कारण है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता संकेतकों तथा उपरोक्त तनावों के खिलाफ प्रतिरोध उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता पर नजर डालना खासतौर से महत्वपूर्ण है।

इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि, भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिये अच्छी तरह तैयार है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विलक्षण जवाब देने की रणनीति के कारण, बहुत अच्छी स्थिति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि, घर खरीदने का यह सबसे अच्छा समय है, जायदाद की खरीद-फरोख्त एकदम बंद सी हो गई थी, महामारी की प्रथम वेव में, पर अब यह गतिविधि पुनः शुरू हो गयी है।
- द्वितीय वेव में खरीद-फरोख्त कुछ कम हुई थी, पर उतनी नहीं जो प्रथम वेव के दौरान हुई थी।
- वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, भारत में महामारी के दौरान ''रिफॉर्म्स'' हुए, जिससे स्टार्टअप खूब पनपे। ये रिफॉर्म ''डिमाण्ड'' को घटाने बढ़ाने के लिये नहीं थे, बल्कि ''सप्लाई साइड'' के रास्ते में अवरोधकों को कम करने के लिये थे।

'हम जहां दो साल पहले थे, अब वहीं पहुंचे हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री, पी. चिदम्बरम ने इकॉनॉमिक सर्वे में बार-बार दोहराई जा रही बात, कि 2021-22 के अन्त में, अर्थव्यवस्था सुधर कर, महामारी के पूर्व की स्थिति (2019-20) में पहुँच जायेगी, का विश्लेषण किया है।

- पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने इकोनॉमिक सर्वे का तीखा विश्लेषण किया।

उन्होंने कहा कि, सीधी भाषा में इसका अर्थ यह है कि 31.3.2022 को जी.डी.पी. उसी स्तर पर होगी, जिस पर 31.3.2020 को थी। इसका अर्थ यह है कि 31.3.2020 को हम जहाँ थे, वहाँ लौटने में हमको दो साल लग गये हैं।

चिदम्बरम ने आगे जोर देते हुये कहा कि, इन दो सालों ने लोगों को कंगाल कर दिया है;

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)